

વિચાર

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने में जुटी योगी सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य कौशल विकास मिशन ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। प्रदेश में उभरते क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मनोरंजन, और नागरिक उद्ययन में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने इन सेक्टर्स में विशेष कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही, जेवर एयरपोर्ट और फिल्मसिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सेक्टर स्किल कार्डिनेल्स के माध्यम से युवाओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूरी भी कर ली गई है। सीएम योगी की यह दूरदर्शी कदम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और मनोरंजन जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में युवाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कर सरकार युवाओं को 'रेडी टू वर्क' बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, नागरिक उद्ययन क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो प्रदेश में एयरपोर्ट के विकास के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता से जेवर एयरपोर्ट और फिल्मसिटी प्रोजेक्ट्स राज्य के विकास का आधार बन रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल्स ने संभावित रोजगार क्षेत्रों की पहचान कर ली है, और अब प्रशिक्षित युवा इनके क्रियान्वयन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट से एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जबकि फिल्मसिटी नोएडा में मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देगी, जिससे मीडिया और प्रोडक्शन से जुड़े युवाओं को फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट और फिल्मसिटी से जुड़े प्रशिक्षण से युवा तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाएंगे। यह कदम राज्य की जीड़ीपी में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को कम करेगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिल रहा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को मुफ्त और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य हर युवा को उसके कौशल के आधार पर रोजगार देना है।

अगड़ी जातियों के खिलाफ राहुल गांधी का हृष्टा बोल, कांग्रेस को किस रस्ते पर ले जायेगा?

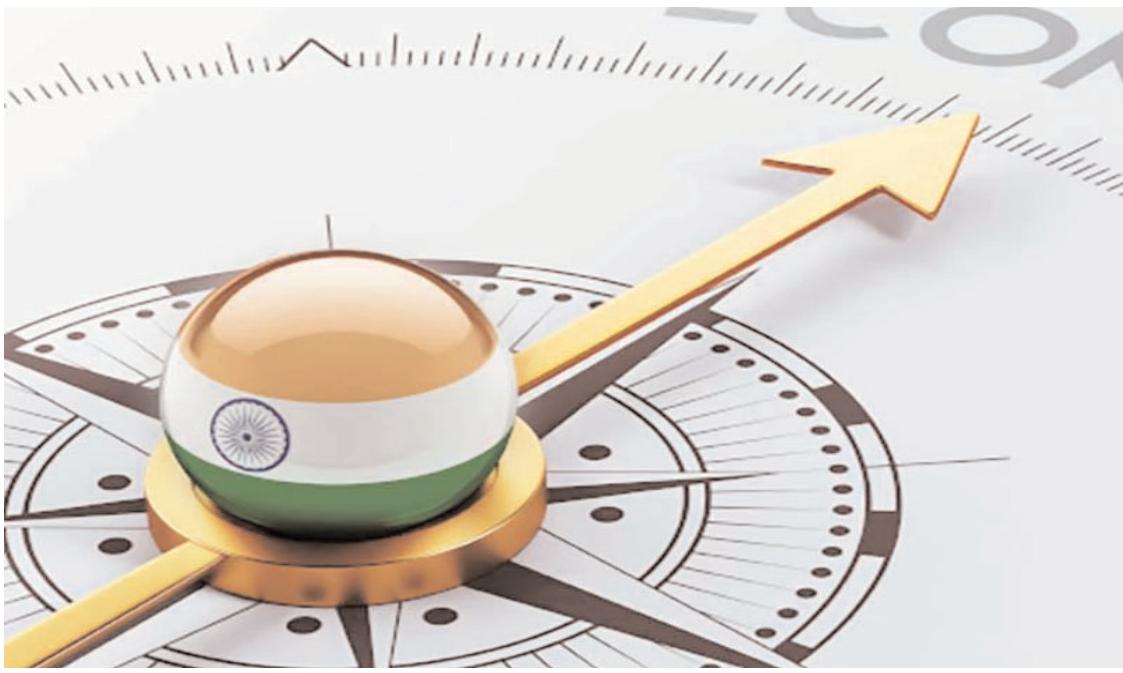
बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम जनीतिक दल इस विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है, जिसमें विधायिकों की संख्या के आधार पर बीजेपी नंबर वन की भूमिका में है। नहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस स्सरे नंबर की बड़ी पार्टी है। हालांकि यह एक तथ्य है कि कांग्रेस के नेता विपक्षी गठबंधन के लिए महागठबंधन शब्द की

जाय इंडिया गठबंधन का ही प्रयोग करने नगे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के जनाधार को लगातार प्रदाने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। पर्व 2025 में ही राहुल गांधी अब तक निर्णय बार बिहार जा चुके हैं। अपने मिशन बेहार के तहत राहुल गांधी सोमवार (7 भूमप्रैल) को बिहार की धरती पर थे। पेछले कुछ महीनों के दौरान उनकी मात्राओं को बात करें तो यह राहुल गांधी ना तीसरा बिहार दौरा था। इससे पहले राहुल गांधी 18 जनवरी और 4 फरवरी

को बिहार के दौरे पर गए थे। लेकिन अपने बिहार दौरे के दौरान, गहुल गांधी ने सोमवार को जिस अंदाज में अपर कास्ट यानी अगड़ी जातियों पर उमला बोला, वो सबके लिए काफी व्याँकने वाला रहा। गहुल गांधी ने कहा के नेताओं ने बिहार को जातियों के आधार पर खंड-खंड बांटने का काम किया है। रही-सही कसर नीतीश कुमार ने ओर्बीसी में से इबीसी और दलितों में से महादलितों को निकाल कर पूरी कर दी है। ऐसे में गहुल गांधी कांग्रेस के

भारतीय अर्थव्यवस्था पर टैरिफ युद्ध का नहीं होगा अधिक प्रभाव

दिनांक 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप द्वारा, विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयातित उत्पादों पर की गई टैरिफ सबंधी घोषणा के साथ ही अंततः अमेरिका द्वारा पूरे विश्व में टैरिफ के माध्यम से व्यापार युद्ध छेड़ दिया गया है। अभी, अमेरिका ने विभिन्न देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर विभिन्न दरों पर टैरिफ लगाया है। अब इनमें से कई देश अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर रहे हैं, जैसे चीन ने अमेरिका से चीन में आयात होने वाले उत्पादों पर दिनांक 10 अप्रैल 2025 से 34 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है। टैरिफ के माध्यम से छेड़ गए व्यापार युद्ध का भारत पर कोई बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ने की सभावना कम ही है। दरअसल, अमेरिका ने विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है और साथ ही कुछ उत्पादों के आयात पर फिलहाल टैरिफ की नई दरें लागू नहीं की गई हैं। टैरिफ की यह दरें 9 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।



विभिन्न देशों से अमेरिका में आयात होने वाले उत्पादों पर 10 प्रतिशत की दर से न्यूनतम टैरिफ लगाया गया है। साथ ही, कुछ अन्य देशों यथा चीन से आयातित उत्पादों पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। इसी प्रकार, वियतनाम से आयातित उत्पादों पर 46 प्रतिशत, ताईवान पर 32 प्रतिशत, थाईलैंड पर 36 प्रतिशत, भारत पर 26 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया पर 25 प्रतिशत, इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत, स्थिट्जरलैंड पर 31 प्रतिशत, मलेशिया पर 24 प्रतिशत, कम्बोडिया पर 49 प्रतिशत, दक्षिणी अफ्रीका पर 30 प्रतिशत, बांगलादेश पर 37 प्रतिशत, पाकिस्तान पर 29 प्रतिशत, श्रीलंका पर 44 प्रतिशत और इसी प्रकार अन्य देशों से आयातित वस्तुओं पर भी अलग अलग दरों से टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने की है। कुछ उत्पादों जैसे, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, एनजी, बुलीयन एवं अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स को अमेरिका में आयात पर टैरिफ के दायरे से बाहर रखा गया है। अमेरिका का मानना है कि वैश्विक स्तर पर अन्य देश अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं के आयात पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका में इन देशों से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर अमेरिका द्वारा बहुत कम दर पर टैरिफ लगाया जाता है अथवा बिलकुल नहीं लगाया जाता है। जिससे, अमेरिका से इन देशों को निर्यात कम हो रहे हैं एवं इन देशों से अमेरिका में आयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार, अमेरिका का व्यापार घाटा असहनीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ, अमेरिका में विनिर्माण इकाईयां बंद होकर अन्य देशों में स्थापित हो गई हैं और इससे अमेरिका में रोजगार

के नए अवसर भी निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। अब ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका को पुनः विनिर्माण इकाईयों का हब बनाने के उद्देश्य से अमेरिका को पुनः महान बनाने का आह्वान किया है और इसी संदर्भ में विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि अमेरिका में आयातित उत्पाद महंगे हों और अमेरिकी नागरिक अमेरिका में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने की ओर प्रेरित हों।

वर्तमान में बढ़े हुए टैरिफ का बोझ अमेरिकी नागरिकों को उठाना पड़ेगा और उन्हें अमेरिका में महंगे उत्पाद खरीदने होंगे, क्योंकि नई विनिर्माण इकाईयों की स्थापना में तो वक्त लग सकता है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन तुरंत तो बढ़ाया नहीं जा सकता अतः जब तक नई विनिर्माण इकाईयों की अमेरिका में स्थापना हो एवं इन विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन शुरू हो तब तक अमेरिकी नागरिकों को महंगे उत्पाद खरीदने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। इससे अमेरिका में एक बार पुनः मुद्रा स्फीति की समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं व्याज दरों के कम होने के चक्र में भी देरी होगी, बहुत सम्भव है कि मुद्रा स्फीति को कम करने की दृष्टि से एक बार पुनः कहीं व्याज दरों के बढ़ने का चक्र प्रारम्भ न हो जाए।

लम्बे समय में जब अमेरिका में विनिर्माण इकाईयों की स्थापना हो जाएगी एवं इन इकाईयों में उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा तब जाकर कहीं मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाया जा सकेगा। विभिन्न देशों से आयातित उत्पादों पर टैरिफ सम्बन्धी घोषणा के साथ ही, डॉलर पर दबाव पड़ना शुरू भी हो चुका है एवं अमेरिकी डॉलर इंडेक्स घटकर 102 के स्तर पर नीचे आ गया है जो कुछ समय पूर्व तक लगभग 106 के स्तर पर

A photograph of Rahul Gandhi, leader of the Indian National Congress, speaking at a political rally. He is standing behind a podium decorated with yellow garlands and a banner with the text 'न्याय का धर्म' (Nyaya ka Dharm). He is gesturing with his right hand while speaking into a microphone. In the background, there is a large projection screen showing a black and white photograph of Mahatma Gandhi. To the right, a red banner is partially visible with the text 'THE CONSTITUTION OF INDIA'. In the foreground, several other political leaders are seated, including a woman in a pink sari and men in white shirts.

कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने और कांग्रेस के जनाधार को मजबूत बनाने के लिए प्रोबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित और नहिलाओं की बात करें, तो इसमें कुछ भी अल्प नहीं है।

लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय और वर्षभरे पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रौढ़ वर्तमान में भी पार्टी आलाकमान की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी से अगड़ी जातियों को लेकर इस तरह की भाषा की उम्मीद तो कर्तई नहीं की जा सकती है। नबकि कांग्रेस और खासतौर से गांधी परिवार ने बीड़ीएम अर्थात् बी से ब्राह्मण दम्पत्ति तमाम अगड़ी जातियों को जोड़ा जाता है), डी से दलित और एम से मुस्लिम फॉमूले के आधार पर दशकों तक देश पर राज किया है। बिहार में भी इसी फॉमूले के आधार पर दशकों तक कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं।

यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि दलित और ओबीसी मतदाताओं को एक साथ नहीं साधा जा सकता। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद यूपी के दलितों ने अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया था। बिहार में भी लालू यादव अपनी ही पार्टी के दिग्गज दलित नेता और बिहार के दम्पत्ति जातियों के दिमाक में

आ गया था। इसी प्रकार अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों की 10 वर्ष की बांड यील्ड पर भी दबाव दिखाई दे रही है और यह घटकर 4.08 के स्तर पर नीचे आ गई है, यह कुछ समय पूर्व तक 4.70 के स्तर से भी ऊपर निकल गई थी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़नी प्रारम्भ हो गई है एवं यह पिछले चार माह के उच्चतम स्तर, लगभग 85 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर, पर आ गई है। ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ सम्बंधी लिए गए निर्णयों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर लम्बी अवधि में तो हो सकता है परंतु छोटी अवधि में तो निश्चित ही यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को विपरीत रूप से प्रभावित करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकी पूँजी बाजार (शेयर बाजार) केवल दो दिनों में ही लगभग 10 प्रतिशत तक नीचे गिर गया है और अमेरिकी निवेशकों को लगभग 5 लाख करोड अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। इतनी भारी गिरावट तो वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान ही देखने को मिली थी। यदि यही स्थिति बनी रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहीं मंदी की चपेट में न आ जाय। यदि ऐसा होता है तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। अतः ट्रम्प प्रशासन का टैरिफ सम्बंधी उक्त निर्णय अति जोखिम भरा ही कहा जाएगा।

जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ तो विपरीत असर होगा ही।

इस संदर्भ में किए गए विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आ रहा है कि बहुत सम्भव है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए 26 प्रतिशत के टैरिफ़ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक विपरीत प्रभाव नहीं हो। क्योंकि, एक तो भारत से अमेरिका को नियंत बहुत अधिक नहीं है। यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र लगभग 3-4 प्रतिशत ही है। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत पर निर्भर नहीं है एवं यह विभिन्न उत्पादों की आंतिक मांग पर अधिक निर्भर है। भारत से सकल घरेलू उत्पाद का केवल लगभग 16 प्रतिशत (वस्तुएं एवं सेवा क्षेत्र मिलाकर) ही नियंत किया जाता है। दूसरे, भारत से अमेरिका को नियंत किए जाने कुछ उत्पादों को उक्त टैरिफ़ व्यवस्था से फिलहाल मुक्त रखा गया है, जैसे फार्मा उत्पाद, सेमीकंडक्टर, स्टील, अल्यूमिनियम, ऑटो, ताम्बा, बुलीयन, एनर्जी आदि। संभवतः इन उत्पादों के भारत से अमेरिका को होने वाले नियंत पर कुछ भी असर नहीं होने जा रहा है। तीसरे, भारतीय कम्पनियों (26 प्रतिशत टैरिफ़) को रेडीमेड गार्मेंट्स के अमेरिका को नियंत में पड़ोसी देशों, यथा, बांग्लादेश (37 प्रतिशत टैरिफ़), पाकिस्तान (29 प्रतिशत टैरिफ़), श्रीलंका (44 प्रतिशत टैरिफ़), वियतनाम (46 प्रतिशत टैरिफ़), चीन (34 प्रतिशत टैरिफ़), इंडोनेशिया (32 प्रतिशत टैरिफ़), आदि के साथ अत्यधिक स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। परंतु, उक्त समस्त देशों से अमेरिका को होने वाले रेडीमेड गार्मेंट्स के नियंत पर भारत की तुलना में अधिक टैरिफ़ लगाए जाने की घोषणा की गई है। अतः इन देशों से रेडीमेड गार्मेंट्स के अमेरिका को नियंत भारत की तुलना में महंगे हो जाएंगे, इससे रेडीमेड गार्मेंट्स के क्षेत्र में भारत के लिए लाभ की स्थिति निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि उत्पादों के नियंत भी भारत से अमेरिका को बढ़ सकते हैं। यदि किन्हीं क्षेत्रों में भारत को नुकसान होता हुआ दिखाई भी देता है तो भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे राजनैतिक संबंधों के चलते भारत को अपने उत्पादों के लिए नए बाजार तलाशने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी, अमेरिका सहित भारत के यूरोपीयन देशों, ब्रिटेन एवं खाड़ी के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सम्पन्न करने हेतु वातान्तीर्ण लगभग अंतिम दौर में पहुंच गई हैं, इसका लाभ भी भारत को होने जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शीघ्र ही मोनेटरी पॉलिसी के माध्यम से रेपो दरों में परिवर्तन की घोषणा की जाने वाली है। भारत में चूंकि मुद्रा स्फीति की दर लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है अतः भारत में रेपो दर में 75 से 100 आधार बिंदुओं की कमी की घोषणा की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत में कुछ कमी सम्भव होगी, जिसके चलते भारत में निर्मित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

अपना कब्जा जमा लिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए वहां बहुत ही कम स्कोप बचता है। कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि अगड़ी जातियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर, राजनीति का सफर शुरू करने वाली मायावती भी पूर्ण बहुमत हासिल कर अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री तभी बन पाई थी, जब उन्होंने अगड़ी जातियों को भी बसपा के साथ जोड़ा था। बिहार में दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी ने पहले ही बड़ा दांव खेल दिया है। ऐसे में अगर वह गांधी परिवार के पुराने विनिंग फॉर्मूले पर अमल करते हुए अगड़ी जातियों को लुभाने की कोशश करते तो कांग्रेस का संगठन और ज्यादा

मजबूत होता नजर आता। बिहार में वर्ष 2022 में कराए गए जाति सर्वे में आए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में सर्वांगीन की कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा यानी 15.52 प्रतिशत है। वहीं दलितों की कुल आबादी 19.65 प्रतिशत यानी 2.56 करोड़ है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में अगड़ी जातियों और दलितों की बड़ी आबादी को लुभाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी को हराने के नाम पर मुसलमान भी कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। बता दें कि, बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी 17.7 प्रतिशत है। ऐसे में राहुल गांधी फिर से बीड़ीएम फॉमूले के तहत कांग्रेस के लिए मजबूत वोट बैंक बनाने की शुरुआत कर सकते हैं।

